



VISIONIAS

INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)/GENERAL STUDIES (Paper-II) (2423)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time Allowed: Three Hours

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

सामान्य अनुदेश

इस प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका में 55+1 पृष्ठ हैं। प्रश्न-पत्र, क्यू.सी.ए. पुस्तिका के अंत में संलग्न है, जो अलग (वियोज्य) किया जा सकता है और उम्मीदवार परीक्षा के उपरान्त अपने साथ ले जा सकते हैं।

रफ कार्य के लिए, इस पुस्तिका के अंत में खाली पृष्ठ दिया गया है।

पुस्तिका प्राप्त होने पर, कृपया यह जांच कर लें कि इस क्यू.सी.ए. पुस्तिका में कोई कमी न हो, फटा हुआ पृष्ठ न हो अथवा कोई पृष्ठ गायब न हो इत्यादि। यदि ऐसा हो, तो इसके बदले नई क्यू.सी.ए. पुस्तिका प्राप्त कर लें।

General Instructions

This Question-Cum-Answer (QCA) Booklet contains 55+1 pages. Question Paper in detachable form is available at the end of the QCA Booklet which can be taken away by the candidate after examination.

For rough work, blank page has been provided at the end of this Booklet.

On receipt of the Booklet, please check that this QCA Booklet does not have any shortcomings, torn or missing pages etc. If, so, get it replaced with a fresh QCA Booklet.

(उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा/To be filled by the Candidate)

पंजीकरण सं./Registration No. : 0801934

अभ्यर्थी का नाम/Name of Student : Manisha Dharve

माध्यम: हिंदी/अंग्रेजी
Medium: Hindi/English

Hindi

तारीख
Date

26/08/23

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II) GENERAL STUDIES (Paper II)

केंद्र
Centre Bhai Joga Singh
School

निरीक्षक के हस्ताक्षर
Invigilator's Signature

[Signature]

महत्वपूर्ण अनुदेश उम्मीदवारों को नीचे उल्लिखित निर्देश सावधानी से पढ़ लेने चाहिए। किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों को मिलने वाले अंकों में कटौती, उम्मीदवारी रद्द या आयोग के परवर्ती परीक्षाओं के लिए वर्जित करने इत्यादि के रूप में दण्डित किया जा सकता है।	Important Instructions Candidates should read the undermentioned instructions carefully. Violation of any of the following instructions may entail penalty in the form of deduction of marks, cancellation of candidature, debarment from further Examination of the Commission etc.
1 (क) अपना पंजीकरण सं. एवं अन्य विवरण केवल प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) में उम्मीदवार के लिए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। (ख) इस पुस्तिका में अन्यत्र कहीं भी अपना नाम, पंजीकरण सं., मोबाइल नं., पता अथवा प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) संख्या न लिखें जिससे आपकी पहचान का खुलासा हो।	(a) Write your Registration Number and other details only in the space provided in the Question-Cum-Answer (QCA) Booklet for candidates. (b) Do not disclose your identity in any manner such as, by writing your Name, Registration number, Mobile number, Address, Question-Cum-Answer (QCA) Booklet No. etc. elsewhere in the Booklet
2 अपनी प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में कहीं भी प्रश्नों के वास्तविक उत्तर के अतिरिक्त कुछ न लिखें जैसे कि कोई कविता/दोहा, अभद्र या अपमानजनक अभिव्यक्ति इत्यादि और न ही कोई ऐसा चिन्ह/निशान बनाएं जिसका उत्तर से सम्बन्ध न हो।	Do not write in the QCA Booklet anything other than the actual answer such as couplet, obscene, abusive expression etc., nor put any sign/mark having no relevance to the answer.
3 परीक्षक को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रार्थना/धमकी भरी बातें न लिखें।	Do not make any direct/indirect appeal/threat to the examiner.
4 उत्तर अस्पष्ट अथवा गंदी लिखावट में न लिखें। इस प्रकार के उत्तर का मूल्यांकन नहीं भी किया जा सकता है।	Do not write answers in bad/illegible handwriting. Such answers may not be evaluated.
5 उत्तर स्याही में ही लिखें। उत्तर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग न करें, हालांकि आरेख, चित्र इत्यादि बनाने के लिए पेंसिल का उपयोग किया जा सकता है।	Write answers in ink only. Do not use pencil for writing the answers. However, pencil may be used for drawing diagrams, sketches, etc.
6 प्रवेश पत्र में उल्लेख किए गए माध्यम के अलावा अन्य किसी माध्यम में उत्तर न लिखें। अधिकृत और अनधिकृत की मिली जुली भाषा का भी उपयोग न करें।	Do not write answers in medium other than the authorized medium in the Admission Certificate. Do not use mixed language either i.e. authorize and unauthorized media together for writing answers.
7 प्रश्नों के उत्तर ठीक उसके नीचे दिए गए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर लिखे गए उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।	Write answer at the specific space (right below the question) only. Answers written elsewhere at unspecified places in the booklet shall not be evaluated.
8 यदि आप अपने किसी उत्तर को रद्द करना चाहते हैं तो उसे पेन से काट दें तथा उस पर "रद्द" लिख दें, अन्यथा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है।	If you wish to cancel any work, draw your pen through it and write "Cancelled" across it, otherwise it may be valued.

कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use	कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use
परीक्षक के हस्ताक्षर Signature of Examiner(s)	

प्राप्तांक के विवरण (परीक्षक द्वारा भरा जाए)/ Marks Details (To be filled by the Examiner(s))

प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks		प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks	
1			11		
2			12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		
उप-योग (A) Subtotal (A)			उप-योग (B) Subtotal (B)		
सकल योग (A+B) / GRAND TOTAL (A+B)					



VISIONIAS

INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)/GENERAL STUDIES (Paper-II) (2423)

निर्धारित समय: तीन घंटे

Time Allowed: Three Hours

अधिकतम अंक: 250

Maximum Marks: 250

प्रश्न-पत्र संबंधी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

कुल बीस प्रश्न दिए गए हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखिए।

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.

All questions are compulsory.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Answers to Questions No. 1 to 10 should be in 150 words, whereas answers to Questions No. 11 to 20 should be in 250 words.

Keep the word limit indicated in the questions in mind.

Any page or portion of the page left blank in the Questions-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

1.

उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से, चर्चा कीजिए कि पर्यावरणीय दबाव समूह भारत में पर्यावरण नीतियों के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी और अनुक्रियाशीलता को कैसे बढ़ाते हैं। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
With suitable examples, discuss how environmental pressure groups enhance public participation and responsiveness with regard to environmental policies in India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को
इस स्थिति में
नहीं लिखना
चाहिए
Candidates
must not
write on
this margin

पर्यावरणीय दबाव समूह हैं पर्यावरणीय
हित समूह का भाग होते हैं जो सरकारी
नीतियों, योजनाओं व कार्यक्रमों की पर्यावरण
के अनुसार व संदर्भ में प्रभावित करने की
कोशिश करते हैं।

पर्यावरणीय नीतियों में सार्वजनिक भागीदारी
बढ़ाने के:-

① जागरूकता बढ़ाकर लोगों को
(जागरूक) प्रदान करने का कार्य करते

[उदा०] पर्यावरण व विज्ञान के द्वारा
रिपोर्ट जारी करना

② सम्मेलन, कोंग्रेस, सम्मेलन जिससे
लोग पर्यावरणीय नीतियों के संदर्भ में
सरकार से मांग करे।

[उदा०] बंदना शिवा का धाम
नव धाम कोंग्रेस समिति

जाफा की मांग करता।

उम्मीदवारों को
इस हार्डिंग में
नहीं लिखना
चाहिए
Candidates
must not
write on
this margin

अनुक्रियाशीलता बढ़ाना

- (1) विरोध प्रदर्शन, नीतियों के प्रति
ऊलटपुट में लागू होने का कार्य
[उदा०] शाहबाज के कोयला खनन के
विरोध दबाव सत्र
- (2) सरकारी नीतियों के मूल्यांकन में
[उदा०] पर्यावरण प्रभाव आकलन नीति
के संशोधन के दौरान
- (3) सरकार से पर्यावरण अनुकूल नीति
निर्माण हेतु मांग
[उदा०] जल विविधता संरक्षण हेतु

पर्यावरणीय दबाव समूह पर्यावरणीय धारा को
बढ़ावा देने का कार्य करते हैं किन्तु
वित्त पोषण, विकास की उपाय, राजनीतिकरण,
अंतर्राष्ट्रीय दस्तवेज के कारण विवादित
उद्देश्यों का भी जन्म देते हैं।

2.

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय द्वारा सेक्स वर्क को एक 'पेशे' के रूप में स्वीकार किया जाना, भारत में सेक्स वर्कर्स के लिए बुनियादी अधिकार और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है। परीक्षण कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The recent acknowledgment of sex work as a 'profession' by the Supreme Court is merely the first step in ensuring basic rights and equality for sex workers in India. Examine. (Answer in 150 words)

उम्मीदवारों को इस कक्ष में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

10

सेक्स वर्क एक व्यापार का स्वरूप है जिसमें शारीरिक संबंधों के बदले पैसे की लेन-देन होता है।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय का महत्व

- (i) व्यापार के रूप में 'सेक्स वर्क' को शामिल किया जातः व्यापार के सिद्धांतों का पालन हो पाएगा। (अनु० 19)
- (ii) सेक्स वर्क का शोषण रुकेंगा
 - पुलिस द्वारा दायरा चकलाधारों ने
 - ग्राहक द्वारा उत्पीड़न पर मानव दर्ज हो सकेगा। (अनु० 23)
- (iii) स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच बढ़ेगी (अनु० 31)
 - HIV / AIDS के मानव कर्म होंगे।

9. पुनर्विपरी व १० पुनर्वसि के लिए
तंत्र व विगानी तंत्र सुद्ध कत!
इह (आपाद, हचिषाद लच्छरी, मनी लोन्डि)
का गहजोई कत होगा)
(DPSP के अनु० ५७)

अल्प प्रयास जा करना आवश्यक

(विधायी) → हासजोई लोगी की तरह इनके
शाका के विरुद्ध विशेष कानून आवश्यक

नीतिगत व योजनागत

→ विशेष नीति का निर्माण

→ यह सिम वर्क की शिक्षा, लाभा, ,
काराल-प्रशिक्षण हनु योजना निर्माण

अवधारालक उपाय

→ लोगों को लैंगिक शिक्षा व संवेदनशील
बनाना

→ राज्य द्वारा 'स्पेशल एरिया' निर्माण जिससे
अधिकारों का संरक्षण हो

'सिमा वर्क' बनाज के अस्तित्व के
लायही सुद्ध ई कत. इले ईवु ईवु दिवज
बनाने के बजस (विनिमय आवश्यक ई)

3.

भारत में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने और कानूनी जागरूकता फैलाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSAs) द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Discuss the role played by District Legal Services Authorities (DLSAs) in providing free legal aid and disseminating legal awareness in India. (Answer in 150 words)

10

उम्मीदवारों को इस खण्ड में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारतीय संविधान का अनुच्छेद -

39 ड निःशुल्क कानूनी सहायता तक
प्रभावी पहुँच का प्रावधान करता है सभी
संसर्ग में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम

1962 का निर्माण किया गया

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा

निःशुल्क शुल्क कानूनी सहायता प्रदान
करने में भूमिका :-

(i) जिला अदालत, सत्र न्यायालय
डीवाणी अदालत, जमानदारी न्यायालय
पीड़ित पक्षों को निःशुल्क शुल्क
कानूनी सहायता प्रदान करता

(ii) वकीलों तक प्रभावी पहुँच करवाता

(iii) सरकारी व अदालती दस्तावेजों व
पैपर वर्क में प्राथमिकी की सहायता

करना।

कानूनी जागरूकता कार्य

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(i) सैमिनार, सम्मेलन, सम्मेलनों का आयोजन जिससे कानूनी कार्य की एक कानूनी व्यवधान के प्रति जागरूकता बढ़े।

(ii) निःशुल्क विधिक सहायता का व्यवधान

(iii) महामात्र के रूप में कार्य करना

कानून की राह

कानूनी जागरूकता

सहायता प्रदान करना

↓
→ सोशल मीडिया
इंटरनेट का उपयोग
→ PRI की मदद लेना

↓
→ डिजिटल जानकारी
→ पब्लिस कार्य को बढ़ावा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
समाज के वंचित वर्गों व संवेदनशील
वर्गों तक प्रभावी पहुँच हेतु वित्तीय सहायता
तकनीक उपयोग का सहारा लेकर बेहतर
कार्य कर सकते हैं।

"कुछ लोगों के हाथों में शक्ति के संकेंद्रण के कारण, कॉलेजियम प्रणाली अपनी ही सफलता का शिकार हो गई है, जिससे इसकी वैधता पर सवाल उठने लगे हैं।" टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

"The collegium system has become a victim of its own success, with the concentration of power in the hands of a few, leading to questions about its legitimacy." Comment. (Answer in 150 words)

10

उम्मीदवारों को
इस खण्ड में
नहीं लिखना
चाहिए
Candidates
must not
write on
this margin

कॉलेजियम प्रणाली न्यायिक नियुक्ति
प्रणाली का अंग है जिसमें न्यायपालिका के
मुख्य न्यायाधीश व पवरिष्ठतम न्यायाधीश
एक ही इलाका उद्भव द्वितीय न्यायाधीश
केस से माना जाता है।

कॉलेजियम प्रणाली की सफलता

(i) न्यायिक नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप
को कम किया

[उदा०] 1980 के दशक में नियुक्तियों
का राजनीतिकरण देखा गया था

(ii) शक्ति के प्रयत्नकारण विद्वानों को

पालन किया क्योंकि न्यायिक कार्य में
न्यायपालिका की भूमिका होनी चाहिए।

(iii) कार्यपालिका के साथ न्यायपालिका
के टकराव को नष्ट किया।

बेधता पर सवाल

उम्मीदवारों को
इस हार्डिंग में
नहीं लिखना
चाहिए
Candidates
must not
write on
this margin

- (i) पारदर्शिता का अभाव क्योंकि नायिक नियुक्ति की प्रक्रिया के आधार सार्वजनिक नहीं।
 - (ii) नियुक्तियों में नायपालिका का एकाधिकार जो शक्ति प्रयुक्त करने के कार्रवाईयिक कार्य में हस्तक्षेप है।
 - (iii) भाई-भतीजावाद व परिवारवाद व अंकल जज को बढ़ावा।
- उदा. - 254 परिवारों के बीच
न्यायाधीश के पदों का वितरण
उच्च न्यायपालिका में।

आगे की राह

- (i) शक्ति के प्रयुक्त करने दिशांत जो हल
होना का पालन करना।
 - (ii) NJAC को व्यापित करना जिलों
संतुलन हो।
 - (iii) ~~न्याय~~ न्यायाधीशों की नियुक्ति के
आधार को सार्वजनिक करना।
- संविधान की संरक्षण के तप के न्यायपालिका
की स्वतंत्रता मिली हुई किंतु इसका check &
Balance भी आवश्यक है।

5.

"सिविल सेवा सुधारों को वर्तमान दौर की चुनौतियों से निपटने के लिए भर्ती और मानकीकृत प्रशिक्षण से आगे बढ़ाया जाना अनिवार्य है।" विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

"Civil services reforms must go beyond recruitment and standardised training to cope with the present day challenges." Analyse. (Answer in 150 words)

10

उम्मीदवारों को
इस वॉशिंग में
नहीं लिखना
चाहिए
Candidates
must not
write on
this margin

सिविल सेवा सेवा सुधारों के कारण

सिविल सेवा की भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण,
चयन, सेवा-मानदंडों, सर्विस रूलों में
संशोधन व परिमर्जन हो रहे हैं।

सिविल सेवा की वर्तमान चुनौतियाँ

(1) औपनिवेशिक मानसिकता के सिविल सेवा
+ रूलबेस्ड की अधिकता
+ प्रशासनिक कार्य का अभाव
+ लालफीताशाही, नाकरशाही,
भाई-भतीजावाद, राजनीतिक दबाव

(2) अज्ञानिता, सह्यनिष्ठा, ईमानदारी जैसे
नैतिक मूल्यों का अभाव

(3) प्रौद्योगिकी तकनीकी व विशेषज्ञता का
अभाव जो IAS, IAS, IAS जैसे लोगों
नें कार्य प्रगति को सीमित करता है।

(4) स्थानीय स्तर व रिमोट एरिया
के प्रति जानकारी नहीं पाने का

भर्ती व मानकीकृत प्रशिक्षण की भूमिका

(i) कुलपति शिक्षित व ज्ञानी लोग (जिन्हें वेवा में काम, विविध विषयों का अध्ययन

उम्मीदवारों को इस हशिप में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(ii) प्रशिक्षण के दौरान अनुभव व फील वर्क द्वारा सीखाया जाना

कुल्य उपानों की कार्य बढ़ना

(i) ~~क~~, भावनात्मक बुद्धिमत्ता (विज्ञान) ताकि जबता से संघाट बेतर, समझा के प्रति समाधानवादी नज़रिया।

(ii) सामान्य के विशेषज्ञ की कार्य बढ़ना ताकि वर्तमान दुग की समझा समाधान हो

(iii) व्युत्प्रेरक से उत्प्रेरक व उत्प्रेरक फंडली हो +) सर्वस दिलीवरी तीव्र, कुशल +) बाधाओं अध्ययन बेतर होगा

(iv) नैतिकता का सम्मिलन करना

जिन्हें वेवा सुधार हेतु 2nd ARC,

होता समिति, बाधवान समिति के व्यापक

(सिफारिश की हुयी उन्हें लागू करने का प्रयास करना चाहिए)

6.

सामाजिक प्रभाव बॉण्ड्स जैसे परिणाम-आधारित वित्त मॉडल में वास्तविक रूप से परिवर्तन लाने और बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता विद्यमान है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Outcome-based finance models such as social impact bonds have the potential to truly catalyse change and deliver socio-economic impact at scale. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस खण्ड में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सामाजिक प्रभाव बॉण्ड्स वित्तीय बाजार के उपकरण हैं जो उन क्षेत्रों में निवेश का विकल्प प्रदान करते हैं जो सामाजिक विकास, सुधार व प्रगति की दिशा में कार्य करें।

उदा० कृषि द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में निवेश हेतु धन जुटाना।

परिवर्तन के स्तर के रूप में

- (i) वित्त का निश्चित स्रोत उपलब्ध होना, परिणामों की निश्चितता बनी रहेगी।
- (ii) कार्य-संस्कृति को बेहतर करेगा व प्रोफेशनलिज्म सिद्ध हो जाएगा।
- (iii) निगरानी व आकलन तंत्र बेहतर होगा। सामाजिक प्रभाव आकलन में सुधार होगा।

सांसाजिक-आर्थिक प्रभाव ड्यन करेगा

- (i) कमजोर व संकेतशील वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, प्रशिक्षण इत्यादि का लाभ मिलेगा।
- (ii) रोजगार सृजन → आम शक्ति → जीवन स्तर में सुधार → HDI रैंक बेहतर होगी
- (iii) मानव संसाधन विकास व सांसाजिक प्रेजी का निगवि रहेगा।
- (iv) साथ नही।

उपाय

- (i) सांसाजिक प्रभाव बांडस की लोकप्रियता बढ़ाने हेतु स्थानीय निकायों व NGO का प्रयोग करना।
- (ii) सोशल इंटरप्र्राइज व सराकटिप को सहयोग देना।
- (iii) पारदर्शिता बढ़ाना तथा वित्त उपलब्धता का रैंच प्रदान करना।

सांसाजिक प्रभाव को कम करने की योजना का वित्त पोडल है जिसमें व्यापक संभावना है।

7.

प्रत्येक वर्ष ग्रेजुएट होने वाली और कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने वाली महिलाओं की संख्या के मध्य का व्यापक अंतराल एक गंभीर समस्या है जिसे हल किए जाने की आवश्यकता है। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The wide gap between the number of females graduating every year and those entering the workspace is an issue of paramount importance that needs to be addressed. Discuss in the context of India. (Answer in 150 words)

उम्मीदवारों को
इस लिखित में
नहीं लिखना
चाहिए
Candidates
must not
write on
this margin

10

भारतीय महिलाओं की लाशरता दर
89.9% (जनगणना-2011) है तथा कार्यक्षेत्र
में भर्तीदारी लगभग 30% (PLFS) है
जो एक विरोधाभास उकट करता है।

जंगल लगेला बकारण

(i) कार्यक्षेत्र में महिलाओं की भर्तीदारी
कम होने का लैंगिक असमानता

(ii) पितृवंशीयता, पितृवंशीयता, पितृत्वता,
पितृस्थानीयता के कारण

→ महिलाएं शिक्षा के लिए शहरों में
चली जाती हैं किंतु रोजगार हेतु नहीं

→ महिलाओं की काम पर भर्ती गलत
माना जाता है (19% परिवारों की
मान्यता)

(iii) कार्यक्षेत्र पर लैंगिक शोषण व
उत्पीड़न /

(iv) शादी के बाद कार्यविल से बाहर होने तथा हाउस वार्ड की भूमिका निभाने

(v) कान्य कारक ने → जो महिलाएं उच्च शिक्षा ने बढ़ रही हैं, उच्च काम वाली नौकरी की तलाश में व्यक्तिगत बेरोजगारी

(vi) लैंगिक वेतन अंतराल

सारकारी प्रयास

(i) POSSE अधिनियम के तहत आंतरिक शिक्षागत सफाई व DMC-Box स्थापना

(ii) लैंगिक वेतन अंतराल को कम करते हुए (DPSP-39 D को लागू किया)

(iii) Startup-Seed Fund व Stand up India में महिलाओं को प्रोत्साहन

कान्य आरक्षक प्रयास

(i) कार्यस्थल को लैंगिक संकेनशील बनाना
→ शौचालय, केच सुविधा

(ii) सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान करना

IMF ने स्वीकार किया की कार्यविल में महिलाओं के बढ़ने के GDP में 27% तक वृद्धि संभव है।

8.

भारत में सामाजिक-आर्थिक नियोजन के लिए एक अद्यतित और कार्यात्मक नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) अनिवार्य है। देश में CRS प्रणाली में सुधार हेतु केंद्र सरकार के हालिया कदम के आलोक में चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

An up to date and functional Civil Registration System (CRS) is essential to the socio-economic planning in India. Discuss in the light of the recent move of the Central government in revamping the CRS system in the country. (Answer in 150 words)

10

उम्मीदवारों को
इस वॉशिंग में
नहीं लिखना
चाहिए
Candidates
must not
write on
this margin

पश्चिम एशिया के साथ भारत के
संबंध दुसरा सम्बन्ध के वर्तमान सम्बन्ध
तक विभिन्न कारणों द्वारा संश्लेषित है
जो-उनके के प्रमुख भू-राजनीति व
भू-कार्यशास्त्र के कारण हैं।

पश्चिम एशिया के साथ भू-राजनीति का
संबंध

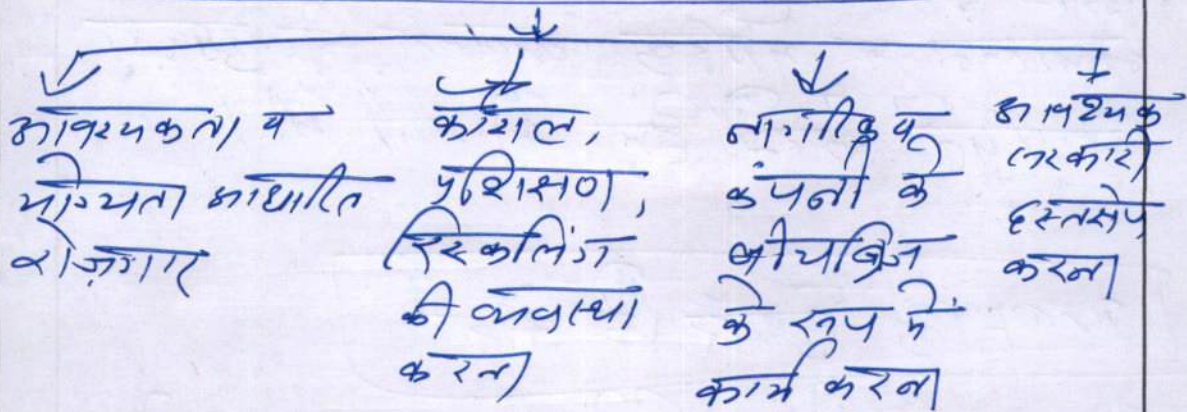


(1) पुरानी भारत का विभाजन धर्म के आधार
पर हुआ था। भारत 'इस्लामिक देशों' के
साथ बेहतर बनाकर पाकिस्तान के साथ
संबंध बेहतर बनाना।

नागरिक पंजीकरण प्रणाली नागरिकों के डेटा बेस की एक व्यवस्था जिसे इनकी नागरिक-सार्विक स्थिति की जानकारी दी गई।

उम्मीदवारों को इस हाथिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

नागरिक व सार्विक नियोजन हेतु



केंद्र-सरकार के हाथिएक

(i) नागरिक पंजीकरण प्रणाली की निर्माण किया गया तथा कार्यविन व मतवल में शामिल लोगों को इनके पंजीकरण करवाया जा रहा।

(ii) ~~निर्माण~~ नियोजन कार्य को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की जा रही ताकि नियोजन किया जा सके।

कार्यविन व मतवल के बीच की समता को बढ़ावा देने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

9.

यदि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के साथ समायोजित होना है तो इसमें सुधार के प्रमुख क्षेत्र कौन-से होंगे? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

What are the key areas of reform if the International Monetary Fund (IMF) has to align with the current economic realities? (Answer in 150 words)

10

उम्मीदवारों को इस हार्निप में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

IMF की स्थापना वर्ष 1945 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था के सुचारु संचालन व मौद्रिक व्यवस्था की सुदृढ़ता स्थापित करने हेतु की गयी थी।

IMF के सुधार के क्षेत्र

(1) कार्रगारी मोड में → इन संस्था में विकासशील व अल्पविकसित देशों का प्रतिनिधित्व नागव्य है अतः कार्यों को लेकर एकतरफा झुकाव दिजता है

(2) ग्रहण व्यवस्था में →

एवरित य आल्पकालिक अहण सुविधा में IMF पीड़ित देशों के उपर अपनी एकतरफा शर्तें थारापित करता जिले देशों की वित्तीय संयुधता का हनन होता है। 135107 मीलंका का हालिया सफल

13) कोरा व्यवस्था में 3 देशों को उनके वित्तीय स्थिति अथवा ऋण के आधार पर ध्यान न देकर कोरा के लिए रिजर्व डेनच में रखी राशि के आधार पर कोरा आवंटित करता।

उम्मीदवारों को इस खण्ड में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

14) रिजर्व फंडी अब कुछ बॉन्डों में केवल पांच देशों की हुआ है जैसे अमेरिकन डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, रेनमिन्बी जबकि भारत 51% सबसे बड़ी आयोजितकर्ता है।

आगे की राह

1) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के रूप में IMF के इन क्षेत्रों में संशोधन अभियान है कि अतिरिक्त कदम के रूप में

→ प्रविण के अनुकूल वित्तपोषण व गैर आवाज को बढ़ावा देना

→ विकासशील देशों की समता निर्माण में सहभागिता करना।

IMF जैसी संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण धारक हैं जिनसे किसी एक देश के हित में संचालित न होकर बहुपक्षीय सुव्यवस्था का पालन करना चाहिए।

10.

हाल के वर्षों में, पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंध भू-राजनीति के दायरे से आगे निकलकर भू-अर्थशास्त्र के आयाम तक पहुंच गए हैं। विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

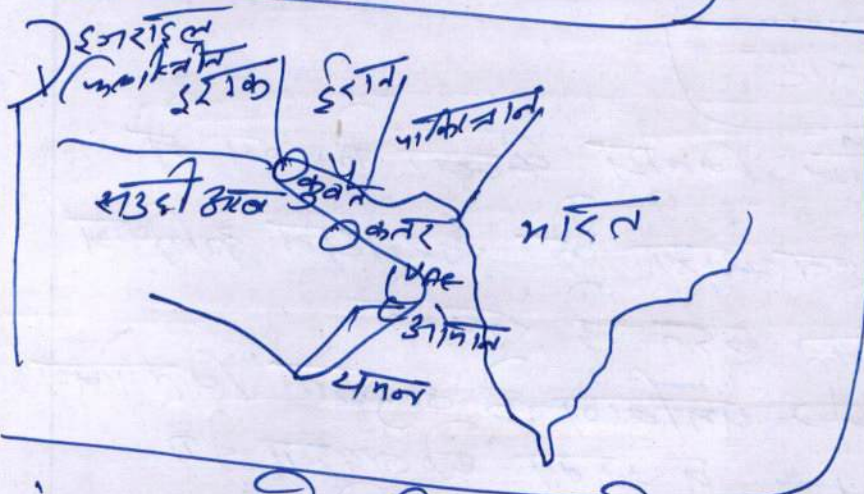
In recent years, India's relationship with West Asia has evolved from the confines of geopolitics to expanse of geoeconomics. Discuss. (Answer in 150 words)

10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत के पश्चिम एशिया के साथ संबंध दृष्टांत लक्ष्यता के वर्तमान समय तक विभिन्न कारकों द्वारा संश्लेषित रहे जिनमें प्रमुख भू-राजनीति व भू-अर्थशास्त्र हैं

भू-राजनीतिक संबंध



(i) भारत के विभाजन के कारण इस्लामिक देशों के साथ के पश्चिम एशिया के संबंध ठीक रखना ताकि पाकिस्तान के हिस्से को संतुलित किया जा सके।

(ii) इजराइल को सार मानता दारैमिक स्तर पर नहीं है, क्योंकि वह अन्य इस्लामिक देशों के संबंध स्थापित होने का भय।

(ii) यूरोप से संबंध के लिए पश्चिम एशिया
बिज के रूप में।

उम्मीदवारों को
इस हॉफ में
नहीं लिखना
चाहिए
Candidates
must not
write on
this margin

भू-ऊर्जाशास्त्र के आधार पर नव संबंध

(i) द्विसह-दूर-दूर सापेक्षता का विकास
प्रदान करते हुए एजराइल ले प्रौद्योगिकी
सहयोग व सहयोग स्थापित करना।

(ii) इरान में चाबहार बंदरगाह निर्माण
ताकि मध्य एशिया तक निर्माण बढ़े।

(iii) इजिप्ट के लिए तेल व गैस के संधि
पश्चिमी देशों में भी विविधीकरण जैसे -
पाक, ईरान, इराक, सऊदी अरब।

(iv) व्यापार (विविधीकरण हेतु पाक के साथ)
सहयोग व व्यापक आर्थिक भागीदारी

(v) आंतरिक प्रेषण का सहयोग करना

(vi) ऊर्ध्व-कुशल रुतबों का नियोजन करना

पश्चिम एशिया के प्रति भारत का रुझान
राष्ट्रहित के अनुसार परिवर्तित हुआ है
जिससे संबंधों में जागरूकता व विश्वास भी
बढ़ा है।

11.

हितधारकों को नवाचार और प्रभावशीलता में वृद्धि हेतु प्रेरित करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की भूमिका महत्वपूर्ण है। टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The role of the Competition Commission of India (CCI) is significant in furthering healthy competitiveness aimed at inspiring stakeholders to innovate and augment effectiveness. Comment. (Answer in 250 words)

15

उम्मीदवारों को
इस सत्र में
नहीं लिखना
चाहिए
Candidates
must not
write on
this margin

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की
स्थापना प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम,
2003 के तहत की गई जिसका उद्देश्य
व्यापारिक स्काधिकार को रोकना तथा
व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना
है।

भूमिका

(i) व्यापारिक स्काधिकार को रोकना है
जिससे कंपनियां नए उत्पादों को बनाने
का विकल्प हड़ती हान नवाचार को
बढ़ावा
[उदा०] मोबाइल व इंटरनेट
क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा

(ii) ग्राहक की शक्ति को महत्व दिया
जाना जिससे ग्राहक उन्मुख
उत्पादों व सेवाओं का निर्माण जिससे

• उठावता को बढ़ावा मिलता ।

उम्मीदवारों को
इस हार्शिए में
नहीं लिखना
चाहिए
Candidates
must not
write on
this margin

(iii) सामग्री व सॉफ्टवेयर की क्वालिटी
का हजान जिले उद्योगों की प्रभाव-
शीलता में गिरा

उदा० कॉस्मेटिक्स में शुगर
कंपनी के प्रोडक्ट ।

(iv) गठजोड़ व कॉर्रल को रोकना जिले
लागत उद्योगी उद्योग व परवर्धित
बनी रहती ।

(v) व्यापिक कर्तों व विचारों को कमियोजित
कर उनके अनुबंध लागू करवाना जिले
कंपनी की प्रभावशीलता व सर्विल डिजिटल
डिलिवरी लागू पर बनी रहती ।

(vi) स्पष्ट मानक, रिशानिर्देशों को
प्रसारित करना व कथि सुचना जारी
करना जिले कॉर्पोरेट गवर्नेंस का
को बेहतर किया जा सके ।

सुधार व सुदृढ़ता हेतु कदम

उम्मीदवारों को
इस कक्ष में
नहीं लिखना
चाहिए
Candidates
must not
write on
this margin

(i) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की
कर्मचारी, वित्त व कामों में अधिक
स्वायत्तता प्रदान करना।

(ii) आयोग में एम्पावैशन् करना
→ नागरिक समाज,
→ SC/ST/OBC महिला वर्ग।

(iii) नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता व
जवाबदेहिता बढ़ाना।

(iv) कॉर्पोरेट गवर्नंस को प्रोत्साहित
करना।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की
श्रुति भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर
की अर्थव्यवस्था बनाने बनाने में काफी
बढ़ गयी क्योंकि न्याय व स्वच्छ
प्रतिस्पर्धा अमलकाल में बनी चहुँपी
है।

"पेड न्यूज का खतरा अक्सर चुनावों के दौरान अपना भयावह रूप दिखाता है।" भारत में पेड न्यूज को एक चुनावी अपराध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

"The menace of paid news often rears its ugly head during elections." Discuss the need for making paid news an electoral offence in India. (Answer in 250 words)

15

उम्मीदवारों को इस इतिहास में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

'पेड न्यूज' को एक खिले हाथ के रूप में देखा जाता है जहाँ जो राजनीतिक छाविमों की गढ़ने अथवा बिगाड़ने के अथवा राजनीतिक दलों के हित में वित्त के बदलते चुपना पुनारित करने का काम करता है।

पेड न्यूज भयावह रूप में

- (1) राजनीतिक छाविमों का निर्माण
- (2) जनता की राय की परिवर्तित करना
- (3) मतदाता व मतदान व्यवस्था को डोकार देने में।
- (4) सत्तावादी अथवा विपक्ष के विरुद्ध डोकारण व विध्वंसालक कार्यों को बढ़ावा देने।
- (5) जातिवाद, क्षेत्रवाद, सामुदायिकता बढ़ाने में।

चुनावी अपराध बनाने की आवश्यकता

उम्मीदवारों को
इस दृष्टि में
नहीं लिखना
चाहिए
Candidates
must not
write on
this margin

(1) धन बल का प्रयोग चुनावों में
करता जो संविधान के स्वच्छ व
स्वातंत्र्य चुनाव के विपरीत है

(2) जनता के सिद्धांत का उल्लंघन
करता क्योंकि अन्य चुनावी प्रत्याशियों को
इसका लाभान्वा भुगताना पड़ता है

(3) जनता के सूचित निर्णय लेने व
माने के अधिकार के नैतिक अधिकार
का हनन जिससे

(4) स्वच्छ लोकतंत्र के प्रतिष्ठित
व्यवस्था जो लोगों को शासन न
देकर शक्तिशाली वर्ग की व्यवस्था
बन कर रह जाती है।

(5) चुनाव आयोग को उचित कार्यवाही
देने शक्ति मिलेगी तथा पुलिस
राजनीतिक हस्तक्षेप के विरुद्ध भी
मानवा दंड कर सकती है।

(७) मानवी न्यायिक अदालत में होगी
अतः राजनीतिक त्याग की बढ़ावा
मिलेगा।

उपाय

- (i) भारतीय प्रेस परिषद की पेंडिंग के
विवाद स्व-नियामक व्यवस्था का
जालन प्रेस से करवाना
- (ii) विचित्र आयोग की ऊपर अधिक अधिकार
ताकि → सोशल मीडिया
→ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पेंड
गुज को रोक जाए
- (iii) राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों की
आचार संहिता व नीति संहिता का जालन
करना अनिवार्य करवाना।

पेंड गुज के विवाद कार्रवाई
हेतु 2nd ARC व बोहरा समिति
ने भी सिफारिशों की हैं उन पर भी
ह्यान दिया जा सकता है।

13.

भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में, न्यायालयों द्वारा उद्धृत 'अनिवार्यता के सिद्धांत' पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Discuss the 'Doctrine of Essentiality' referred to by the courts in the context of religious practices in India. (Answer in 250 words)

15

उम्मीदवारों को
इस हार्डिंग में
नहीं लिखना
चाहिए
Candidates
must not
write on
this margin

न्यायालय द्वारा 'अनिवार्यता का सिद्धांत' उन निर्देशों व मूल्यों को अनिवार्य व आवश्यक मानता है जो धर्म के अनिवार्य धारक रहे हैं।

न्यायिक निर्णय का महत्व

(1) धर्म के अनिवार्य भाग व धारक स्पष्ट होने से धार्मिक प्रथाओं के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

उदा० मस्जिद को इस्लाम का अनिवार्य भाग नहीं माना

(2) न्यायिक निर्णयों के बढ़ावा से जैसा - इलाह लगाजनें प्रति की श्रद्धा के पश्चात् संप्रति पर धर्म पाली का अधिकार न मान कर भाई अथवा भतीजे का माना जाता।

(3) धर्मनिरपेक्ष प्रथाओं व ई-धार्मिक प्रथाओं के राज्य का हस्तक्षेप व प्रभाव बढ़ेगा जिससे सामाजिक-कार्यिक व्याप को महत्व मिलेगा।

उदा० शिवर नठ नामले के अनुवर्धता का विहंग।

(4) समाज की कुप्रथाओं व रूढ़िवादी के संशोधन संभव जैसे - लवरीनामा मंदिर के रजोधर्म के गुजरने वाली महिलाओं को भी प्रवेश दिया गया।
(लवरीनामा मंदिर नामला)

(5) राज्य की धर्मनिरपेक्ष धर्म के मजबूती मिलेगी।

(6) समाज के विविध विहंग को बढ़ावा मिलेगा उदा० हिजाब नामले के हिजाब के अनुवर्ध नहीं नामला जिससे स्कूलों के समाज को बढ़ावा मिलेगा।

चिंता के विषय भी

- (i) न्यायिक कार्रवाई की संभावना
- (ii) धर्मनिरपेक्ष राज्य की छवि पर प्रश्न उठने लगे।
- (iii) धर्म की स्वतंत्रता के नागरिक अधिकारों का उल्लंघन संभव होगा।
- (iv) संस्कृति को परसित छ रखने के अधिकार (अनुच्छेद 29) का हनन होगा।

आगे की राह

- (i) धर्म व राज्य की भारतीय धर्मनिरपेक्षता में स्थिति आपस में होती है। अतः प्रभाव है कि धर्मनिरपेक्षता व धर्म की स्वतंत्रता बनी रही।
- (ii) धर्म के प्रति लोगों की गलत धारणा, खडिगी, परंपराओं को कम करने का कार्य धार्मिक नेताओं द्वारा किया जाना

भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता को मूल ढांचा मानता है तथा धर्म की स्वतंत्रता भी है अतः संतुलन बहाल होगा।

प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सरकार के आकार को सीमित करने की तत्काल आवश्यकता है। क्या आप सहमत हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

As per the recently released report of the Economic Advisory Council to the Prime Minister (EAC-PM), there is an urgent need to limit the size of the government in India. Do you agree? (Answer in 250 words)

वर्तमान सरकार के नीतिगत
कादशी सूतम न्यूनतम प्रकार -
अधिकतम शालन के अनुसार प्रधानमंत्री
की आर्थिक सलाहकार परिषद ने रिपोर्ट
जारी की है।

तत्काल आवश्यकता के पास के तर्क

(i) अलक्षिक मंत्रियों व कार्यपालिका
कर्मचारी ने राजस्व ^{व्यय} बढ़ाने का कार्य
किया।

(ii) संसाधनों का दुरुपयोग होता है -
सरकारी वाहन, स्वास्थ्य भत्ता, पेंशन,
दुरुसा व्यय।

(iii) कार्यों का अतिरिक्त जोड़े बिजली
वि. मंत्रालय, कोयला मंत्रालय,

नवीन व नवीकृतोप नृगालय समी
उर्जा के लिए ही कार्य करते व लाभार्जन
का आभाव है।

उम्मीदवारों को
इस इतिहास में
नहीं लिखना
चाहिए
Candidates
must not
write on
this margin

(iv) पर लोभुपता, अत्याचार, कोनी-
हंजीवाद कम होगा।

(v) दल-बदल को कम करेंगे तथा
राजनीतिक गठजोड़ हतोत्साहित होगा
जैसे - मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री इत्यादि
का प्रचलन करना।

(vi) संसाधन व प्राधिकरण का कुंठिकरण
होगा जिससे अधिकतम सार्वजनिक
होगा।

(vii) विरवाय व चर्चा को धरापा मिलेगा

विपक्ष में तर्क

(i) 1.40 लाख प्रतिनिधि जनसंख्या के
केवल संसद की 15% जनसंख्या
द्वारा कार्यकारी सेवा देना अनुपातिक
रूप में नहीं है।

(ii) शक्ति व संसाधनों का इतिरेक निरंकुशता व तात्कालिकता का प्र बहाल देगा)

(iii) कार्यों का अत्यधिक बोझ होगा तथा क्षेत्र विशिष्ट जानकारी की आवश्यकता को जनता को भुक्तान होगा।

(iv) समावेशी व प्रभावी सरकार के निर्माण हेतु अधिकतम सरकार भी आवश्यकता

संतुलन के प्रभाव

(i) जनसंख्या के अनुसूप कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

(ii) पारदर्शिता व जवाबदेहिता बढ़ाना तथा

(iii) शासन के प्रशासनिक दस्तखत का प्रयोग
→ प्रगति पोरल
→ प्रगति शक्ति पोरल

संविधान के कल्याणकारी राज्य
के आदर्श को परिपूर्ण करने हेतु अधिकतम
शासन जन कल्याण हेतु कानिष्ठ है कते।
सरकार का ठाकार भी आवश्यकता व
विशिष्टता अनुसूप बाँटनीय है

15.

इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस (IoE) योजना की कल्पना भारत में उच्चतर शिक्षा के 'विश्व स्तरीय' केंद्र विकसित करने के लिए की गई थी, लेकिन छह साल बाद भी, यह अभी तक गेम चेंजर नहीं बन पाई है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The Institutions of Eminence (IoE) scheme was conceived to develop 'world-class' centres of higher education in India but six years later, it is yet to become the game changer it was intended to be. Discuss. (Answer in 250 words)

उम्मीदवारों को इस हार्डिग में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

15

इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में की गयी थी ताकि उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व विश्वस्तरीय संस्थाओं का निर्माण किया जा सके। किंतु यह अधिक प्रभावी नहीं रही।

कारण

- (i) उच्च शिक्षा संस्थाओं में अभी भी पित्त के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ग्रांट पर निर्भरता अत्यधिक है। कारण: वित्तिय स्वायत्तता नहीं।
- (ii) विश्वविद्यालयों के लक्ष्य होने के कारण प्रत्येक सत्र, सिलेबस, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण, परीक्षा का आयोजन संभव

नहीं।

उम्मीदवारों को
इस कक्ष में
नहीं लिखना
चाहिए
Candidates
must not
write on
this margin

- [3] शोध व विकास पट्ट निम्न लक्ष्य ने
प्रयोगिकीय जड़ता को स्थापित किया।
- [4] आधारभूत ढाँचा अभी भी ऊर्ध्व
स्थिति में है। विदेशों से विद्यार्थी व
शिक्षा लक्ष्यों में प्रवेश लेने की
उत्साहित नहीं होते।
- [5] अध्ययन - अध्यापन के सीमित डोमेन
का प्रभाव किया जाना।
- [6] लक्ष्यों का राजनीतिकरण किया
जा रहा।

कदम जो आवश्यक हैं

- [1] इंस्टीट्यूशन ऑफ मैननेस
कमिटी को स्पष्ट रेखांकित करते हुए
उनमें सुधार करना तथा संशोधित
मोडल को लागू करना।
- [2] अकेडमी - उद्योग लक्ष्यों को बढ़ावा
देना जिससे बाजार में अक्षरों
में गुणवत्ता का अंतर है।

13] विदेशी शिक्षा संस्थाओं का भारत में प्रवेश हुआ है और उनकी प्रबंधन व प्रौद्योगिकी का उपयोग लेना व अनुभव प्राप्त करना।

14] NAAC द्वारा मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य शिक्षा करना।

भारत जनसांख्यिकीय लॉकरा के कारण कम कुशल कार्यक्षम की राजधानी के रूप में स्थापित होने की संभावना समता रखता है जो उच्च शिक्षा के विश्वस्तरीय गुणवत्ता के बिना संभव नहीं होगा और उपयुक्त प्रमाण आवश्यक है।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) नवोन्मेषी और सुविधाजनक सार्वजनिक सेवाओं की अनुमति देता है, समावेशन या पहुंच संबंधी बाधाओं को दूर करने में मदद करता है तथा रियल-टाइम डेटा की मदद से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाता है। उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Digital Public Infrastructure (DPI) allows for innovative and convenient public services, help overcome inclusion or accessibility barriers, and increase transparency and accountability with real-time data. Discuss with examples. (Answer in 250 words)

15

उम्मीदवारों को इस हॉशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर
डिजिटल रूप में सार्वजनिक कंपनियों के बिजनेस को संचालित करने वाली व्यवस्था है जो सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होती है।

उदा० → COWIN-APP
DIKSHA APP

लाभ

11] नवाचार को बढ़ावा तथा लोगों की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करता है

जैसे - Aadhaar डेटा द्वारा PDS के सुवाधान मिलना।

12] लोगों के कगलारे बगैर तक भी समान व निः शुक्ल रूप से पहुँचाना

उदा० - Bhāim APP

13] वास्तविक स्थिति की हमल दास
जानकारी होने से पारदर्शिता
जवाबदेहीता की बढ़ाया मिलता

13510] - मनरेगा का डिजिटल
मस्टर प्लान

14] हाशिये पर स्थित लम्हे व रिपोर्ट
परिचा के लोगों की जानकारी व
स्थिति को शामिल करता।

13510] Madhukar Dey

15] नागरिक सेवाका के पहुँचाने का
कार्य त्वरित व उच्चोती रूप से
करता तथा

13510] UPI व DBT के तहत
लाभ हलाना तरा

16] भ्रष्टाचार व लालफीताशाही को
कम करता

13510] प्रगति पोरल

प्रभावी बनाने हेतु प्रयास

(1) डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना)

उदा. डेटा सुरक्षा विधेयक पारित करना)

(2) लाइबर डेटा को बढ़ाना)

(3) वॉरनेट कनेक्टिविटी डिजिटल शंकर

पारना व डिजिटल लाइसन्स बढ़ाने का प्रयास करना)

(4) स्वदेशी सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर निर्माण से प्रोत्साहित जिससे औद्योगिक क्रॉस 4.0 में संयुक्तता को बढ़ावा भी मिले।

वर्तमान के तकनीकी युग में डिजिटल प्रबलक इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देशों में तकनीकी संयुक्तता व बाह्य संयुक्तता बढ़ाने के साथ ही लगावशील विकास को ~~बढ़ाने~~ चाहता है करने में सक्षम है।

कानून के अलावा, भारत में 'सभी के लिए स्वास्थ्य के अधिकार' की पूर्ण प्राप्ति हेतु सामाजिक, वित्तीय और बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Besides legislation, the full realisation of the 'right to health for all' in India demands plugging of social, financial, and infrastructural gaps. Examine. (Answer in 250 words)

भारतीय न्यायपालिका ने अनुच्छेद-२ के तहत गरीबों के जीवन के स्वास्थ्य के अधिकार की मान्यता प्रदान की है तथा राज्य का नीति निर्देशक तत्व अनु. ५१ के तहत सभी के स्वास्थ्य के अधिकार को प्रकट करता है।

कानून द्वारा मान्यता देना

- 1] राज्य की विधिक जिम्मेदारी होगी तथा नैतिक जिम्मेदारी के साथ पुष्टि प्राप्त करेगी।
- 2] विधिक अधिकार के रूप में नागरिक दावा कर सकते।
- 3] कनजोर वर्गों का लक्ष्य बन जाएगा।
- 4] न्यायपालिका द्वारा अधिकारों का संरक्षण होगा।

किंतु 'लक्ष्मी के लिए स्वास्थ्य के अधिकार' को उन्निहित करने हेतु राज्य के बाधाओं को भी देखना आवश्यक है।

उम्मीदवारों को इस भाग में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सामाजिक बाधाएँ

(1) 'लैंगिक भेदभाव' महिलाओं के स्वास्थ्य का प्रभाव नहीं।

(2) भ्रूणहारी, कुपोषण, एनीमिया जैसी स्थिति लक्ष्मी को दुर्बल बनाती।

(3) शिक्षा कम होने से जागरूकता नहीं।

(4) जातिवाद व सामुदायिक विभेदताएँ।

वित्तीय बाधा → GDP का केवल 1.5%।

वर्च होता जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के 3% व्यय का लक्ष्य

→ इतने भी 31% शहरी अस्पतालों पर 70% पैसा खर्च व्यय होता जबकि ग्रामीण आबादी को नगण्य पैसा।

बुनियादी ढाँचा

→ पहुँच हेतु परिवहन नहीं, सड़कों का ग्रामीण जाल कम कम। अस्पताल तक पहुँचना कठिन।

→ प्रति डॉक्टर 1445 लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी (WHO मानक है कम) या ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति अनर्था

उम्मीदवारों को इस बाशिरे में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

1 उपाय

लाभानिक	वित्तीय	आवसंरचना
- शिक्षा - पोषण (उत्सा) - आरोग्य सेवाएं - कर करना	- न्यूनतम वेतन - वित्तगत लाभ - व्यापकता	ग्रामीण व शहरी इलाकों में लक्ष्यित प्रदान

1 कानूनी

→ स्वास्थ्य के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मानना व लेवामों हेतु कानून बनाना (उदा. राजस्थान सरकार का शालिया स्वास्थ्य करना)

भारत ने स्वास्थ्य परत विकास लक्ष्य - 3 के तहत लक्ष्य के लक्ष्य जीवन व स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस दिशा में

उपलब्ध आनुमान भारत योजना के रूप में आवश्यक है।

विधायी समर्थन के बावजूद 'थर्ड जेंडर' को अभी तक भारतीय समाज में मान्यता नहीं मिली है। विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
The 'third gender' has not yet been engendered in the Indian society despite legislative nudge.
Analyse. (Answer in 250 words)

थर्ड जेंडर को सुजीन कोर् द्वारा
मान्यता प्रदान की गयी जो LGBTQIA+
समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों) के संरक्षण
कानून 2019 के तहत प्रावधान

- (1) तृतीय लिंग की पहचान को स्पष्ट
करना व स्व-चिह्नित करने की स्वतंत्रता
- (2) इन्हें 03C वर्ग के तहत शैक्षणिक
~~व निष्ठा~~ संस्थाओं में व नियोजन में
कार्रवाई मिलेगी।
- (3) जिला कलेक्टर द्वारा इन्हें जेंडर
प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (4) परिवार के साथ रहने, संपत्ति का
उत्तराधिकार पाने व घर में रह-वास

का अधिकार मिला है,

भारतीय समाज में मान्यता नहीं मिलने
के कारण :-

(1) पारंपरिक रूढ़ियों, परंपराओं व प्रथाओं में इनके व्यक्ति के लोई पर स्वीकार नहीं किया जाना

[2] समलैंगिकता को मौखिक रोग माना जाना

[3] सामाजिक दुराग्रह द्वारा इनका शोषण किया जाना

[4] इनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति इनके हितों को समर्थन नहीं मिलना।

[5] शिक्षा व स्वास्थ्य तक उपायी पहुँच नहीं दिना। MFV / MSDS की कुमेधता

उपाय

(1) समाज को वैज्ञानिक लक्षणशीलता व सिंग साक्षरता प्रदान करना

12] थर्ड जेडर के शिसा के छ. पत्रलि
अधिकार 47)

उदा० उत्तरपुरा सरकार द्वारा
होलजेडर लोगो हेतु विरवविधालय

निति

13] अनपराधिकार को अपराध नहीं मानना
उदा० ~~IPCC~~ को - IPC-1860 की धारा
उमो को अपराधमुक्त किया 117

14] नियोजन व कौशल प्रशिक्षण पर
ध्यान केंद्रित करना

उदा० IAS द्वारा बिंदुल द्वारा
होलजेडर कर्मचारी को कार्यलिपि में

15] ^{नौकरी} ~~बैंगिक वजरीय~~ मातृवर्ग गृह करना।

मासिक लक्षण की विविधता के
वप में थर्ड जेडर के बिकार करत
हए उन्हे लक्षणवैशी विकास को लक्षण के
शामिल करत हेतु लक्षण लक्षणता
वुनिश्चित करना चाहिए।

19.

अन्य कारकों के अलावा, चीन और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों ने भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन (SCO) से अपनी अपेक्षाओं को पूरा करना कठिन बना दिया है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Among other factors, strained ties with China and Pakistan make it difficult for India to fulfill its expectations from the Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Discuss. (Answer in 250 words)

15

उम्मीदवारों को
इस स्थिति में
नहीं लिखना
चाहिए
Candidates
must not
write on
this margin

शंघाई सहयोग संगठन
मध्य एशिया के देशों व रूस, चीन व
भारत के बीच गठबंधन का पहला
ई जी 1/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व
करता है।

भारत की अपेक्षाओं को पूरा करने में
कठिनाई के कारण

- (1) पाकिस्तान द्वारा लगातार संगठन
की सदस्यता में कड़ी सतर्कता के
अंतराधीनकरण ने
- (2) चीन द्वारा उस SCO की अपनी
केंद्रियता में दखलाने करने का
प्रयास किया गया।
- (3) कानूनी, वित्तीय धरणाओं

(14) भारत के पश्चिम देशों के संबंधों
को संतुलित करने की कठिनाई।

(15) S.C. वर्गों का नियमित नहीं
होगा।

उपाय

(1) 'द्विपक्षीय मुद्दों' की बजाय
संघीय हितों को महत्व देना।

(2) शक्ति का लोकतांत्रिकीकरण हासिल
के स्तर पर करना।

S.C. का जीवन संघीय हित की
वृद्धि देगा व भारत के राष्ट्रीय हित
लाभने का अवसर।

उम्मीदवारों को
इस हाशिए में
नहीं लिखना
चाहिए
Candidates
must not
write on
this margin

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी (iCET) पर हाल ही में संपन्न पहल, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनकी साझेदारी में लंबे समय से प्रतीक्षित परिवर्तन का वादा करती है। परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The recently concluded initiative on Critical and Emerging Technology (iCET) between the United States and India promises a long overdue transformation of their partnership in the field of technology. Examine. (Answer in 250 words)

15

उम्मीदवारों को
इस लिफाफे में
नहीं लिखना
चाहिए
Candidates
must not
write on
this margin

संयुक्त राज्य अमेरिका व भारत
के बीच हाल ही में महत्वपूर्ण व
उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल हुई है
जिससे प्रौद्योगिकी क्रांति 4.0 की शक्ति
का दोहन संभव होगा व अंतरराष्ट्रीय
साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा।

लक्ष्य

(1) भारत को USA के प्रौद्योगिकीय
ज्ञान, तकनीक, प्रबंधन, अनुभव
का लाभ।

(2) भारतीय निवासियों व कार्रबिलों के
प्रशिक्षण का विश्वस्तरीय अवसर

(3) क्रिकल तकनीक में विशेषज्ञता
प्राप्त होगी।

14] तकनीकी विशेषज्ञता व कुशलता का लाभ मिलेगा।

15] आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य व (विकसित भारत बनाने के विकल्पों में गृहित होगी)

उम्मीदवारों को इस खांशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उम्मीदवारों को
इस कक्ष में
नहीं लिखना
चाहिए
Candidates
must not
write on
this margin

SPACE FOR ROUGH WORK